

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 462 of 2023

Raja Ram Singh

.....Applicant

Versus

State of U P & Ors.

.....Respondents

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 8 i, e. Central Pollution Control Board (CPCB) in compliance to Hon'ble NGT order dated 02.04.2024 in O A No 462 of 2023, Raja Ram Singh Vs State of U P & Ors.	
2.	Annexure- I A true copy of Gazette of India Notification S.O.1224(E) dated 28.03.2020.	
3.	Annexure- II A copy of Hon'ble NGT order dated 02.04.2024.	

(Nazimuddin)
Scientist 'F'Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
Delhi- 110032.

Date: 22.04.2024

Place: Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 462 of 2023

Raja Ram Singh

Applicant

Versus

State of U P & Ors.

Respondents

Reply on behalf of Respondent No. 8 i, e. Central Pollution Control Board (CPCB)

Most Respectfully submitted as under: -

PRELIMINARY SUBMISSIONS: -

1. That the Respondent No. 8 herein is Central Pollution Control Board (In short referred as "CPCB") which is statutory Board constituted under Section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and has also been entrusted with the functions under The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and The Environment (Prevention and Control of Pollution) Act, 1986.

2. That the present reply is being filed through the Scientist 'F' of Central Pollution Control Board, Delhi. The under signed is competent and empowered to file the present reply on behalf of Respondent No. 8.



3. That the Hon'ble NGT (PB) in OA No. 462/2023 vide order dated-02.04.2024 (uploaded on NGT website on 09.04.2024) in Para 11 directed as below:

“...

5. *Short reply has been filed by respondent no.7-CPCB vide email dated 22.02.2024 without giving any specific response to the question of permissibility of short term mining permit and environmental safe guards relating to the same.*

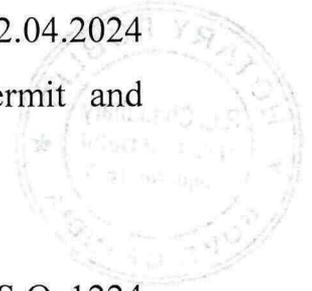
...

11. *Replies/reports be filed by respondents no. 2 (the Director, Geology and Mining, U.P.), 3 (the District Magistrate, Gonda), 4 (UPPCB), 7 (MoEF & CC) and 8 (CPCB) as directed vide order dated 21.12.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date of hearing hereby fixed failing which exemplary costs will be imposed on them for non-compliance of the order of this Tribunal.*



12. *List for further consideration on 24.04.2024. ...”*

4. That it is humbly submitted that an additional reply is being filed in compliance of above-mentioned Hon'ble NGT order dated-02.04.2024 with respect to the permissibility of short-term mining permit and environmental safeguards relating to the same.
5. That it is humbly submitted that Ministry has issued Notification S.O. 1224 (E) dated 28.03.2020 wherein certain cases are exempted from requirement of obtaining Environmental Clearance, including for, “Removal of sand deposits on agricultural field after flood, by farmers”. Such exemption may apply only in case of removal of the sand deposited above surface in the agricultural fields by a flood.



However, mining of the minor minerals, except for activities exempted by the aforesaid notification dated 28.03.2020, require Environmental Clearance as per the EIA Notification, 2006 (and its amendments time to time). Further, the said notifications do not stipulate exemption from Environmental Clearance for short-term mining of the minor minerals as such. A true copy of Notification S.O.1224(E) dated 28.03.2020 is attached as **ANNEXURE-I**.



PRAYER

In view of the above facts and circumstances, it is humbly prayed to the Hon'ble Tribunal that the Hon'ble Tribunal may pass appropriate order in the interest of justice and this answering Respondent no.8 undertakes to abide by the orders/directions passed by this Hon'ble Tribunal in the present Original Application.




Nazimuddin
Scientist 'F'

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 462 of 2023

Raja Ram Singh

.....Applicant

Versus

State of UP & Ors.

.....Respondents

AFFIDAVIT

I, Nazimuddin, working as Scientist 'F' in Central Pollution Control Board, at Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi- 110032, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am fully conversant with the facts of the case and hence, competent and authorized to depose and swear the present affidavit in my official capacity.

That the contents of the annexed reply have been drafted by me and the contents of the same are true and correct on the basis of the record of the case as maintained in the day-to-day affairs of the CPCB and the contents of the short reply may kindly be treated part of this affidavit and the same are not repeated herein for the sake of brevity.



DEPONENT

नाज़िमउद्दीन / Nazimuddin
 वैज्ञानिक 'एफ' / Scientist 'F'
 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 Central Pollution Control Board
 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
 (M/o Environment, Forest And Climate Change Govt. of India)
 परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
 Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

VERIFICATION

22 APR 2024

Verified at Delhi on this day of April, 2024 that the contents of the above reply affidavit are correct and true on the basis of the record of the case as maintained in the day-to-day affairs of the CPCB. Nothing has been concealed therefrom or mis-stated.



DEPONENT

नाज़िमउद्दीन / Nazimuddin
वैज्ञानिक 'एफ' / Scientist 'F'
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(M/o Environment, Forest And Climate Change, Govt. of India)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
22 APR 2024



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942

No. 1088]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्वाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ख का अंतःस्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्विना बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिकांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्विना बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।”;

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज वाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्विना बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।”

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर-2189 (68) / 5 – सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
13. ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।”

[फा. सं. जेड-11013 / 47 / 2018-आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्कर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का. आ. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का. आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016;
33. का. आ. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का. आ. 3977 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का. आ. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का. आ. 5736 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का. आ. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018;
38. का. आ. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019;
39. का. आ. 1960 (अ), तारीख 13 जून, 2019;
40. का. आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020;
41. का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और
42. का. आ. 1223 (अ), तारीख 27 मार्च, 2020।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 1224(E).—WHEREAS, *vide* the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as MMDR Act) has been amended with effect from the 10th day of January, 2020 and, *inter alia*, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances has been inserted;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease;

AND WHEREAS, in pursuance of the aforesaid amendment to the MMDR Act, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006);

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance for borrowing of ordinary earth for roads; and manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, and in supersession of the notification number S.O. 4307(E), dated the 29th November, 2019, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(3) The successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier:

Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease.”;

(ii) in the Schedule, against the item 1(a), in the column (5), after clause (2) of the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(3) The evacuation or removal and transportation of already mined out material lying within the mining leases expiring under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), by the previous lessee, after the expiry of the said lease, shall not form the part of the mining capacity so permitted to the successful bidder, selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder.”;

(iii) for Appendix-IX, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“APPENDIX-IX

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts.
6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.
7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
8. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.
9. Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community.
10. Digging of wells for irrigation or drinking water purpose.
11. Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be.
12. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority.
13. Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity.”

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;

14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E), dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E), dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E), dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E), dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E), dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E), dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E), dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E), dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E), dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E), dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019;
39. S.O. 1960(E), dated the 13th June, 2019;
40. S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020;
41. S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020; and
42. S.O. 1223(E), dated the 27th March, 2020.

Item No.06

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 462/2023

Raja Ram Singh

Applicant

Versus

State of U.P.& Ors.

Respondents

Date of hearing: 02.04.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.**

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Mukesh Verma, Advocate for respondent no. 2-
Mining Department, State of U.P.
Mr. Pradeep Misra Advocate for respondent no. 4-
UPPCB (through VC).
Mr. Sharad Chauhan and Mr. Ravindra Singh,
Advocates for Respondent No. 5-Mr. Satyanayan.
Mr. Hem Chandra Joshi, Advocate for Respondent No.
6-Mr. Umesh Kumar Singh (through VC).
Dr. Sapna Agarwal, Advocate for Respondent NO. 7-
MoEF & CC (through VC).
Mr. Raj Kumar, Advocate for respondent no. 8-CPCB.

Application is registered based on a letter petition received by Post.

ORDER

1. This Tribunal vide order dated 21.12.2023 issued the following interim directions:-

- (i) the Director, Geology and Mining, U.P. and the Member Secretary, UPPCB were directed to file their own affidavits giving detailed reasons justifying selective arbitrary and discriminatory treatment given to some mining lease holders without taking any action against other similarly placed mining lease holders in tabular

format with all relevant particulars with respect to each mining lease holder in the State of Uttar Pradesh.

- (ii) While noticing involvement of question of permissibility of such short term permits MoEF&CC and CPCB were impleaded as respondents no. 7 and 8. As respondent no. 7 was already appearing in the case notice was ordered to be issued to respondent no. 8 and respondents no. 7 and 8 were required to file reply/response with respect to the permissibility of short term permits and environmental requirements/safeguards regarding the same.
- (iii) The Director, Geology and Mining, State of U.P. was directed to file additional reply giving information regarding short term mining permits issued by the District Magistrates/District Mining Officers in the State of U.P. and the procedure followed in respect thereof during last one year.
- (iv) The Member Secretary, UPPCB was directed to file additional reply giving details of cases of short term permits in which CTE/CTO was taken from UPPCB and number of cases in which CTE/CTO was not taken from UPPCB.
- (v) The District Magistrate, Gonda was directed to take over possession of the sand un-authorizedly stored and to dispose of the same by way of open auction and deposit the amount thereby realized with UPPCB for utilizing the above said amount for restoration of environment in the area and to file action taken report in this regard.
- (vi) The Director, Mining and Geology, State of U.P. was directed to issue instructions regarding taking possession of the illegally

mined material and auctioning of the same and deposit of the proceeds with UPPCB for utilization for restoration of environment.

2. Replies have been filed by respondent no. 5 vide email dated 24.02.2024 and by respondent no.6 vide email dated 22.02.2024.

3. The Director, Geology and Mining, State of U.P. and the Member Secretary, UPPCB have not filed their affidavit/additional reply.

4. The District Magistrate, Gonda has also not filed any action taken report.

5. Short reply has been filed by respondent no.7-CPCB vide email dated 22.02.2024 without giving any specific response to the question of permissibility of short term mining permit and environmental safe guards relating to the same.

6. Additional Affidavit has also been filed by respondent no.8-MoEF & CC vide email dated 27.03.2024 but in the additional affidavit reference has been made to stone crushers instead of short term mining in agricultural land for removal of sand deposited by flood.

7. None has appeared on behalf of respondent no. 1-State of Uttar Pradesh and respondent no.3 -DM, Gonda.

8. The proceedings before this Tribunal cannot be treated as part of adversarial litigation where the concerned defendants may opt out to remain absent and suffer ex-parte proceedings. On the other hand, the State and its instrumentalities are under constitutional and statutory obligations to ensure compliance with environmental norms and, therefore, the State and its instrumentalities have to ensure submission of their replies/response with relevant details and also their representation

through duly authorised representatives/Counsel before this Tribunal. Since, State of Uttar Pradesh and some of its instrumentalities were not generally appearing before this Tribunal and filing their replies/response in response to the notices served on them, the matter was brought to the notice of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and learned Advocate General, Government of Uttar Pradesh for issuance of appropriate instructions for compliance with notices issued by this Tribunal and submission of reply/response and ensuring representation through their authorized representative/counsel before this Tribunal, as may be required.

9. Learned Counsel for respondents no. 2, 4, 7 and 8 seek adjournment for filing of affidavits/additional affidavit/additional reply/action taken report.

10. Non-appearance before this Tribunal and also failure to file replies/reports within specified time warrants imposition of exemplary costs on the defaulting respondents but in view of earnest request made by the learned Counsel for the defaulting respondents and by taking lenient view as an exceptional measure we refrain from passing any order for payment of costs by defaulting respondents.

11. Replies/reports be filed by respondents no. 2 (the Director, Geology and Mining, U.P.), 3 (the District Magistrate, Gonda), 4 (UPPCB), 7 (MoEF & CC) and 8 (CPCB) as directed vide order dated 21.12.2023 at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date of hearing hereby fixed failing which exemplary costs will be imposed on them for non-compliance of the order of this Tribunal.

12. List for further consideration on 24.04.2024.

13. This Tribunal noticed in its order dated 07.11.2023 that the case involves the question of permissibility of issuance of short term permits without EC from SEIAA, consent from UPPCB and compliance with SSMMG, 2016 and EMGSM, 2020 and issued ad interim injunctive direction that no short term permit be granted for mining of minor mineral (sand, morrum etc.) without EC from SEIAA, consent from UPPCB and compliance with SSMMG, 2016 and EMGSM, 2020.

14. In Civil Appeal No. 1628-1629/2021 titled as Noble M. Paikada Vs. Union of India the Hon'ble Supreme Court has held that completely, unguided and blanket exemption granted by item 6 in appendix-IX to the requirement of obtaining in EC notification dated 14.09.2006 to be arbitrary and violative of article 14 of the Constitution of India.

15. The questions of permissibility of issuance of short term permits, procedure to be followed for grant of short term permits and environmental safe guards to be imposed need to be examined.

16. The case will be taken up on the date fixed for arguments in respect of the above referred environmental questions.

17. The ad interim injunctive order dated 07.11.2023 shall continue till further orders to the contrary and no short term permit be granted for mining of minor mineral (sand, morrum etc.) without EC from SEIAA, consent from UPPCB and compliance with SSMMG, 2016 and EMGSM, 2020.

18. A copy of this order be sent to the Chief Secretary, Government of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Secretary, MoEF & CC,

Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Member Secretary, UPPCB, Member Secretary, CPCB, District Magistrate, Gonda and learned Advocate General, Government of Uttar Pradesh by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 02nd 2024
ag